

एस- 12013/3/2015- एसबीए- पार्ट (1)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय  
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

चौथा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,  
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,  
नई दिल्ली, 110003

दिनांक- 27.04. 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव/ सचिव/ ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव  
सभी राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र

**विषय: विभागीय वेबसाइटों पर डाटा को शेयर करते समय आईटी अधिनियम, 2000 और आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन के प्रति जागरूकता बरतना।**

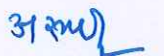
महोदया/महोदय,

यह पत्र उपर्युक्त विषय पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिनांक 24 अप्रैल, 2017 के अ.शा. प.सं. एनआईसी/डीडीजी (एसबीएम)/आईटी एक्ट/2017 से संबंधित है (प्रति संलग्न) जिसमें यह ध्यान में लाया गया है कि व्यक्तिगत पहचान अथवा सूचना अर्थात् जनसांख्यिकी विवरणों सहित आधार संख्या दर्शाना आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का खण्डन करता है जिसके लिए 3 वर्षों तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान है।

2. इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेखनीय है कि बैंक खातों के विवरणों (व्यक्तिगत डाटा संवेदनशील होने के नाते) सहित वित्तीय सूचना का प्रदर्शन करना भी आईटी अधिनियम 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करना है जिसके तहत उल्लंघन करने वाले को प्रभावित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति के रूप में क्षति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

3. उपर्युक्त को देखते हुए सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र और उनके संबंधित मंत्रालयों/ विभागों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वेबसाइटों पर डाटा प्रकाशित/शेयर करते समय सभी सावधानियां बरतें और आईटी अधिनियम 2000 और आधार अधिनियम 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय



(अरुण बरोका)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं.: 011-24362192

फैक्स सं.: 011-24369831

ईमेल: arun.baroka@nic.in

प्रतिलिपि:

1. एसबीएम समन्वयक (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
2. एनआईसी- मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु



अरुणा सुन्दराराजन, एस.एस.  
Aruna Sundararajan, I.A.S.

सचिव  
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
भारत सरकार  
Secretary  
Ministry of Electronics &  
Information Technology (MeITY)  
Government of India

D.O. No. NIC/DDG(SBS)/ITACT/2017  
Dated: 24<sup>th</sup> April 2017

**Sub: Sensitization on compliance of IT Act, 2000 and Aadhaar Act, 2016 while Data Sharing in the departmental Websites**

Dear Secretary,

Kindly refer to the Office Memorandum (OM) No. 10(36)/2015-EG-II (Vol-V) Dated: 25.03.2017 on Data Sharing - Compliance of IT Act, 2000 and Aadhaar Act, 2016. The OM is self-explanatory and aims for maintenance of secrecy with respect to personal identity or information of residents.

2. It has come to notice that there have been instances wherein personal identity or information of residents, along with Aadhaar numbers and demographic information, and other sensitive personal data such as bank details etc. collected by Ministries/ departments, state departments for the administration of welfare schemes etc. have been published online.

3. Publishing identity information i.e. Aadhaar number along with demographic information is in clear contravention of the provisions of the Aadhaar Act, 2016 and constitutes an offence punishable with imprisonment upto 3 years. Further, publishing of financial information including bank details, being sensitive personal data, is also in contravention of provision under IT Act, 2000 with violations liable to pay damages by way of compensation to persons affected.

4. In view of the above, the Web Information Managers (WIMs) of all Ministries/ Departments and State Government departments may kindly sensitize the Ministries/ Departments and State Government departments respectively and also take all precautions while publishing/ sharing data on their websites, ensuring compliance of the IT Act, 2000 and Aadhaar Act, 2016 with immediate effect. Further, they are also requested to review their website contents/ quality as per the standard guidelines of GIGW, IT Act 2000 and Aadhaar Act 2016. It is also advised that any such contents already published or still appearing publicly, may be discontinued with immediate effect

With regards,

Yours sincerely,

(Aruna Sundararajan)

To

Secretaries of all the Ministries/Departments, Government of India